

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 1427

गुरुवार, 09 दिसम्बर, 2021/18 अग्रहायण, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

कूज पर्यटन को बढ़ावा देना

1427. श्री वि. विजयसाई रेड्डी:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश में कूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसी योजना को क्रियान्वित कर रही है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में कोई कूज पर्यटन परियोजना शुरू करने का विचार है; और
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): कूज पर्यटन की क्षमता को स्वीकार करते हुए, पर्यटन मंत्रालय ने कूज पर्यटन को एक आला पर्यटन उत्पाद के रूप में चिह्नित किया है।

कूज पर्यटन सहित पर्यटन स्थलों और उत्पादों का विकास और संवर्द्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासन की जिम्मेदारी है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय 'पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' योजना के तहत पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति पर कूज पर्यटन और नदियों के साथ कूजिंग सहित पर्यटन के विकास के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास हेतु तटीय परिपथ को पंद्रह थीमेटिक परिपथों में से एक के रूप में अभिज्ञात किया है और धन की उपलब्धता, परस्पर प्राथमिकता और योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन की शर्त पर प्रत्येक वर्ष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से प्राथमिकता के आधार पर विविध पर्यटन परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें कूज पर्यटन से संबंधित घटक शामिल किए जा सकते हैं।

उपरोक्त के अलावा, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला को भी कार्यान्वित किया है, जो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 14,500 किलोमीटर संभावित नौवहन जलमार्ग की क्षमता का दोहन करके देश में आर्थिक विकास को गति देना है। सागरमाला कार्यक्रम के तटीय नौवहन और आईडब्ल्यूटी स्तंभ के तहत, विभिन्न परियोजनाएं हैं जो विशेष रूप से क्रूज यात्री परिवहन को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं।

(ग) और (घ): भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य में क्रूज पर्यटन/तटीय परिपथ से संबंधित निम्नलिखित परियोजनाओं को मंजूरी दी है:-

पर्यटन मंत्रालय :

पर्यटन अवसंरचना विकास योजना के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता		
परियोजना		स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
विशाखापत्तनम बंदरगाह के बाहरी बंदरगाह में चैनल बर्थ क्षेत्र में क्रूज-सह-तटीय कार्गो टर्मिनल का निर्माण		38.50
स्वदेश दर्शन योजना (तटीय परिपथ)		
i)	काकीनाडा - होप आइलैंड - कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य - पसारलापुडी - अडुरु - एस यनम - कोटिपल्ली का विकास	67.84
ii)	नेल्लोर - पुलिकट झील - उब्बलमडुगु जलप्रपात - नेलापट्टू-कोठाकोडुरु - मायपाडु - रामतीर्थम - इस्कापल्ली का विकास	49.55

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय :

सागरमाला	
परियोजना	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के बाहरी बंदरगाह में चैनल बर्थ पर क्रूज टर्मिनल बर्थ और टर्मिनल भवन का निर्माण	96.05
